Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 24-03-2005
Participants : Acharia Shri Basudeb,Kumar Shri Shailendra,Paswan Shri Ram Vilas,Salim Shri Mohammad,Paswan Shri Ram Vilas,Dasgupta Shri Gurudas

Title: Shri Basudeb Acharia called the attention of the Minister of Steel to the situation arising out of inordinate delay in merging Indian Iron and Steel Company (IISCO) with Steel Authority of India and steps taken by the Government in this regard.

12.04 hrs.

MR. SPEAKER: Now, we shall take up Item No.16 - Calling Attention.

Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I call the attention of the Minister of Steel to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereof:

> "Situation arising out of inordinate delay in merging Indian Iron and Steel Company (IISCO) with Steel Authority of India Limited and steps taken by the Government in regard thereto."

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य और गुरूदास दासगुप्ता, संसद सदस्यों द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) का विलय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.(सेल) में करने में हो रहे असाधारण विलम्ब से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में ध्यान आकृट किया है। मैं सदन के सामने निम्नलिखित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी " इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को)" को 1918 में निगमित किया गया था। वर्ा 1952 में विलयन संबंधी कई बार विचार-विमर्शों के पश्चात् इस्को बर्नपुर में इसकी इस्पात उत्पादक इकाई, गोवा और चिरैया में निजी लौह अयस्क खानों, चासनाला, जीतपुर और रामनागौर में कोयला खानों, कुल्टी में एक निजी फाउंड्री और पाइप निर्माण संयंत्र तथा विपणन संगठन के साथ एक शीर्ा एकीकृत इस्पात कम्पनी बन गई। भारत सरकार ने 1972 में इस कम्पनी के प्रबन्धन का तथा 1976 में इस्को के शेयरों का अधिग्रहण किया। वर्ा 1978-79 में इस्को के शेयर सेल को अन्तरित कर दिए गए थे और इस्को सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी बन गई थी।

प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, संयंत्र और उपकरण के पुरानेपन, पुरानी प्रौद्योगिकी, आवश्यक पूंजी आदान के अभाव आदि के कारण इस्को कई वर्ाों से हानि उठाती रही है। यद्यपि, इस्को के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रस्ताव तैयार किये गये थे, किन्तु निधियों के अभाव के कारण कोई भी योजना शुरु नहीं की जा सकी।

रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप जून, 1994 में इस्को को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) को सौंप दिया गया था और अगस्त, 1994 में इसे एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोिात कर दिया गया था। इस्को के पुनरुद्धार के लिये कई योजनाओं की परिकल्पना की गई थी किन्तु किसी को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

भारत सरकार ने सेल के लिये फरवरी, 2000 में एक वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन पैकेज अनुमोदित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार इस्को को सेल/ भारत सरकार के द्वारा 1946.17 करोड़ रुपये के ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव किया गया था और भारत सरकार ने कम शेयर धारिता वाली सेल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इस्को के परिवर्तन का अनुमोदन किया था। तथापि, ये प्रयास सफल नहीं हो सके।

भारत सरकार ने जून, 2002 में इस्को के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इसके आधार पर इस्को सेल ने इस्को के पुनरुद्धार के लिये एक पुनरुद्धार पैकैज तैयार किया, जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) को प्रस्तुत किया था। बीआईएफआर ने दिनांक 20.11.2003 को इस्को के लिये एक पुनरुद्धार योजना मंजूर की, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्ों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र एवं उपस्करों और आवश्यक पूंजीगत निवेश के अभाव के चलते इस्को को हानि हुई है। तथापि, कंपनी ने 2003-04 से लाभ कमाना शुरु किया है (27.00 करोड़ रुपये) और 2004-05 के पहले नौ महीने में लगभग 125.00 करोड़ रुपये का अनंतिम लाभ अर्जित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार इस्को की संचित हानि 955.00 करोड़ रुपए है और ऋणात्मक निवल मूल्य 620.00 करोड़ रुपए है।

पुनर्संरचना पैकेज के कार्यान्वयन और बेहतर बाजार परिस्थितियों के परिणामस्वरूप सेल ने वर्ा 2003-04 में अब तक का सर्वाधिक 2512 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पश्चात्) अर्जित किया है। 2004-05 के प्रथम 9 माह के दौरान सेल ने अब तक सर्वाधिक 4139 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पश्चात्) अर्जित किया है।

इस्को के निपादन में और सुधार करने के लिये संयंत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना आवश्यक है। इस्को की वर्तमान स्थिति इसके अनुकूल नहीं है। विलयन किये जाने से इस्को का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। विलयन किये जाने पर इस्को के उपलब्ध कच्चे माल के संसाधनों का इस्को और सेल, दोनों के द्वारा इटतम उपयोग किया जा सकता है। सेल की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं तथा इस्को की खानों/कोयला खदानों, बड़े पैमाने पर उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं और अच्छी कार्य संस्कृति तथा उपलब्ध क्षमता का उपयोग करते हुये सेल और इस्को बेहतर तरीके से क्षमता का विस्तार और संयंत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन कर सकते हैं। अत: प्रस्तावित विलयन से सेल और इस्को, दोनों को लाभ होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार भी इस्को को दी जाने वाली राहतें और रियायतें विलयन के बाद भी सेल को देने पर सहमत हो गई है। बीआईएफआर द्वारा इस्को के पुनरुद्धार के लिये अनुमोदित पैकेज में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस्को को दी जाने वाली रियायतों का लाभ लगभग 315.24 करोड़ रुपये था।

मामले पर विस्तारपूर्क विचार किया गया है और प्रस्ताव है कि इस्को का सेल में विलयन कर दिया जाये। सेल बोर्ड और इस्को बोर्ड ने इस्को के सेल में विलयन किये जाने का सिद्धांन्तत: अनुमोदन कर दिया है। इस समय, सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the Indian Iron and Steel Company is the premier steel manufacturing unit of our country. … (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : आप इस बात का धन्यवाद तो दीजिये क्योंकि आपकी बात मान ली गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : उसके लिये मैं बाद में कहूंगा।

MR. SPEAKER: You will get that from the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Perhaps, this is the first steel making industry in our country. When this industry was closed, it was taken over by the Government of India. Subsequently, it was nationalised in 1978 and the shares of IISCO were transferred to SAIL.

But after IISCO became the subsidiary of the Steel Authority of India, no substantial investment was made for the revival of IISCO, for the renewal of over-aged and worn-out machinery. In spite of that, IISCO has earned profit in the year 2003-04, which was Rs. 27 crore. This year, as stated by the Minister of Steel, during 2004-05, it is expected that IISCO would earn a profit of about Rs. 127 crore

BIFR has given a final verdict and the Government of India has also agreed to the package approved by BIFR. That was done more than a year ago. In the month of June, the Minister of Steel, Shri Ram Vilas Paswanji visited Burnpur. He visited almost all the steel plants after becoming the Minister of Steel. In his visit at the Burnpur, he announced that the Government would actively consider the merger of IISCO with Steel Authority of India. It is the demand of all the workers and the people of West Bengal that IISCO should be merged with Steel Authority of India.

MR. SPEAKER: He has agreed.

SHRI BASU DEB ACHARIA : But Sir, it should urgently be done. The steel market is booming now. SAIL has earned a profit of more than 2,500 crore this year.

MR. SPEAKER: Therefore, ask the question relating to its implementation.

SHRI BASU DEB ACHARIA :I am coming to the question.

Sir, Visvesvaraya Iron and Steel Company Limited, Bhadravati was also one of the subsidiaries of Steel Authority of India Limited. It was merged long back in the year 1996 when the United Front Government was there at the Centre. That Government had taken the decision of its merger with IISCO.

So, my question is that when , in principle, the Ministry of Steel has agreed for merger of IISCO with SAIL, why is it being delayed. There should be some timeframe fixed. Unless this merger is finalized and approved by the Cabinet, this will not be materialized.

MR. SPEAKER: A statement has already been made on the floor of the House and I believe, the Cabinet has to do it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : What he has stated is that ‘the proposal is under active consideration of the Government.’ I have received a letter of 14th March, in reply to my letter, wherein he has stated that ‘it is under active consideration of the Government.’ He met the Chief Minister of West Bengal on 30th September, most probably. I was also there in the meeting with that Chief Minister, and so far as I remember, there also, he had announced that the Government had taken a decision for merger of IISCO with Steel Authority of India. But why is it being delayed?

Another problem is that…

MR. SPEAKER: I think, ‘active consideration’ means it will be implemented soon.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, Rs. 965 crore is the accumulated loss in addition to the loans and liabilities. In case of Bhadravati Steel Plant, when the merger was materialized, it was done on a clean slate. I would like to know from the hon. Minister whether in this case also, IISCO’s merger with SAIL be done on a clean slate.

There is one more point. Indian Iron and Steel Company is not only ideally located but it has its own captive coal mines and it has its own coal washeries.

The best quality coal is produced in IISCO's washery at Chesnala. It has a captive iron ore mine in Chiriya. The best quality iron ore is available at Chiriya mines. But the Jharkhand Government refused to renew the agreement that was there since long.

MR. SPEAKER: I am sure, they would look into all these things.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know from the hon. Minister whether – it is a major mineral – the State Government has any power or authority to say that they would not allow the iron ore or coal to move from one State to another. This will not only affect IISCO, but it will also affect the entire steel industry. So, I would like to know whether the Government of India would take it up with the Jharkhand Government so that there may not be any difficulties in regard to renewal of the agreement which is there in the Chiriya Iron Ore Mines.

I would urge upon the Government – not only in the interest of the workers, but also in the interest of the people of West Bengal and also the economy of South Bengal which depends on IISCO because 15,000 workers are working there, in addition to about 3,000 contract workers who are mostly from my constituency – not only to actively consider this, but also to take immediate decision in regard to the merger of IISCO with SAIL. Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Hon. Speaker, Sir, I do not doubt and I should not doubt the intention of the Minister. The Minister says that it is under active consideration. Kindly bear with me. The question of revival of IISCO was discussed in this House and in the other House also for the last 10 years and one after the other, the Ministers had made a statement that it would be done. Never did they say that it would not be done. Even the partners were chosen in order to put funds for revival. Unfortunately it has not been done, as a result, the losses incurred by IISCO have been heavily mounting from year to year.

The statement that the hon. Minister has made has many lacunae. I should not say that they are serious, but it has lacunae because the basic question is about merger. The Government has not yet decided this question because decision to merge involves some questions: what is going to happen to the Government's money? has the Ministry of Finance concurred? It does not depend on the Ministry of Steel only; there is a Steel Development Fund from which he could get money, but it depends on the decision of the Ministry of Finance. क्या माननीय मंत्री जी आपकी इस बारे में वित्त मंत्री जी से कोई बात हुई है? क्या वित्त मंत्री जी आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? Without getting the approval from the Ministry of Finance, if he makes a statement in the House that it would be done and it is under active consideration, etc., it would appear to me – I do not say unrealistic – as an uncertainty. So, if uncertainty continues, IISCO will not be revived. This is my first question to him.

The second one is, what about the bank loan? There is a large volume of bank loan. Will the Ministry of Steel approach the banks and the Ministry to get concessions for one time settlement as the banks generally do, in the case of other companies? Has it been done?

Thirdly, has SAIL made a plan for investment? Only the Board has agreed.

That is not enough. How much of money they are going to put in, what is the revival package and has the revival package been technically evaluated by the Ministry of Steel in collaboration with

SAIL. Without these modalities, the biased statement of the Minister may appear to be a promise far away from performance.

My fourth question is, the Minister is reviving Burnpur. What about Kulti? Kulti was an integrated part of ISCO. The Ministry has disbanded Kulti and stopped production there. Even the employees quarters do not have any water or electricity. They have left Kulti in lurch, only alluring Burnpur, that at the cost of Kulti, Burnpur will be revived. Hon. Minister""s statement does not contain a single sentence about the future, workers and revamping of Kulti.

Lastly, I must say that the Government of West Bengal has done its job. It has agreed to give the concession. What about the Government of India? It has got the prior approval of the Government of West Bengal. Instead of giving your assurance, you are putting the cart before the horse because the nodal agency is not the Government of West Bengal but the Government of India. Therefore, Sir, I would like to request the hon. Minister to honour his statement to every letter and word that he has uttered and he has to assure the House what is the time frame within which these lacunae will be sought to be solved, particularly the most difficult hurdle of getting the approval of the Finance Ministry. How long will it take to evaluate technically the revival programme? What SAIL is going to do with regard to the money? What is the total money involved?

MR. SPEAKER: You have said all that earlier also.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : We have always been given the assurances by the successive governments. My senior colleague, at present the Minister of Heavy Industry, is not here. He held a meeting with the trade unions. He made a plan. You, Sir, were also there. But it was not done. Therefore, we would like to say, भााण बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन परफॉरमेंस के बारे में क्या होगा ? मेहरबानी कर के हाउस को बताइए, नहीं तो, the statement that you have made will be taken with a pinch of salt.

MR. SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, you may just put the question. Please do not make a speech. You have not given the notice in time.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने में हुए अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य और माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने यहां प्रश्न किए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के पास यह मामला बहुत समय से विचाराधीन है और इसमें इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ? दूसरी बात यह है कि मजदूरों के हित में वे क्या सोच रहे हैं ? आज मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। क्या उन्हें अन्य जगह रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'इस्को` का मामला काफी समय से लटका हुआ था। अभी हमारे साथी ने जैसा कहा कि हम लोग मई, 2004 में सरकार में आए हैं और मेरे सरकार में आने के बाद, मैंने सबसे पहला काम किया कि देश के जितने भी स्टील के प्लांट हैं उन सबका विद्यार्थी के तौर पर दौरा किया और जानने की कोशिश की कि कहां किस प्रकार की कठिनाई है। उसी दरमियान जून में जब मैं बर्नपुर गया, तो मैंने वहां की स्थिति देखी। मैंने पाया कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है, रॉ-मटीरियल है और माइन्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास फंड्स की कमी है। 'सेल` को नई सरकार आने के बाद काफी मुनाफा हुआ और उसका मुनाफा आगे और भी बढ़ रहा है। मैंने उसी समय कहा था कि मजदूरों के हित में, देश के हित में और प्रदेश के हित में हमें 'इस्को` का 'सेल` में मर्जर स्वीकार्य है।

जून आने के बाद बातचीत चल रही थी कि प्राइवेट सैक्टर को दिया जाए - यह किया जाए, वह किया जाए - जिससे मैं चिन्तित हो गया। तब मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी से बात की। मैं 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल चला गया और वहां के मुख्य मंत्री जी से बात की। वहां श्री बसुदेव आचार्य जी थे तथा और भी हमारे साथी थे, सेल के चेयरमैन और अधिकारी भी थे।

मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, 15 मिनट के अंदर सारी बात की। मैं नहीं समझता हूं कि किसी मंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में इतनी संक्षिप्त, शोर्ट वार्ता हुई होगी। मैंने 15 मिनट के अंदर उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका मर्जर हो जाए। आपकी जो शर्त एवं कंडीशन है, उसे आप लगाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं तैयार हूं। तब मैंने उसी समय कहा कि इस चेप्टर को क्लोज़ कीजिए, हम लोग केन्द्र में जाकर कार्यवाही करेंगे। चीफ मिनिस्टर तथा हमने प्रैस वालों के सामने आकर घोाणा कर दी कि हम सैद्धांतिक रूप से मर्जर के पक्ष में हैं और इस पर कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद जून आने के बाद, मैंने तुरंत सेल और इस्को के बोर्ड को आदेश दिया। आपको मालूम है कि इस तरह की फोरमेलिटीज अदा करनी ही पड़ती हैं।

महोदय, मैंने उन्हें कहा कि आप अपने बोर्ड से मर्जर के प्रस्ताव को पास कराएं। हम जून में बर्नपुर गए थे, 31 अगस्त को मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई और अगस्त के बाद, 27 सितम्बर को पहली इस्को के बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति व्यक्त कर दी गई। अगले दिन 28 सितम्बर को सेल ने अपने बोर्ड में मर्जर के प्रस्ताव को पास कर दिया। उसके बाद अक्तूबर में हमारे पास प्रस्ताव आया और उसके बाद मर्जर का प्रस्ताव मंत्रालय में आया। मंत्रालय में आने के बाद आप जानते हैं कि थोड़ा-बहुत कर्मचारियों का इंटरैस्ट होता है, पैसे का मामला था, कि पैसा कौन दे, कौन नहीं दे। फिर हम झमेले में नहीं जाना चाहते थे। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएं या कहीं और जाएं, इन सारी चीजों को हमने अपने आप देखने का काम किया और देखने के बाद निर्णय लिया कि हम इसे केबिनेट में भेजेंगे, इस प्रस्ताव को रिकमेंडेशन के साथ कैबिनेट भेजेंगे। आप जानते हैं कि केबिनेट में भेजने से पहले विभिन्न संबंधित मंत्रालय और जो मिनिस्ट्रीस होती हैं, उनसे सहमति लेनी पड़ती है या टिप्पणी करनी पड़ती है कि उनकी क्या राय है। उसके लिए विभिन्न मंत्रालयों को हमने उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया। हमें लगता है कि जल्दी ही यह काम हो जाएगा। हम विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क में लगे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो स्वयं केबिनेट में जाकर टिप्पणी कर सकते हैं। उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इस सारे प्रोसेस को करके केबिनेट की एप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा।

आप जानते ही हैं कि उसके बावजूद भी समय लगेगा। केबिनेट की एप्रूवल के बाद, फिर इसे सेल के बोर्ड में एप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। उसके बाद वहां से डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स की एप्रूवल के लिए जाएगा, फिर तीनों कम्पनियों के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद कम्पनी अफेयर्स से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद फिर बीआईएफआर में जाएगा और अंत में फाइनल कम्पनी के साथ में मर्जर हो जाएगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा यह जो मुद्दा है, इसे हम तीन महीने के अंदर कर लेंगे और दस साल की बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सारा प्रोसेस तीन महीने के अंदर, केबिनेट वगैरह वाला हो जाएगा। उसके बाद सारे के सारे प्रोसेस में मेक्सिमम छ: महीने का समय लगेगा, लेकिन इस साल के अंत तक पूरे का पूरा मर्जर कर लेंगे, सेल के साथ इसका मर्जर हो जाएगा - इसकी हम घोाणा करते हैं। यह कम्पनी वगैरह का मामला है। हमारा अपना जो काम है, मैंने उसका टारगेट दो महीने का रखा है, लेकिन चूंकि सदन में घोाणा करने का मामला है, इसलिए मैं मेक्सिमम तीन महीने, और 30 दिन का समय सदन से मांगता हूं और यहां इसकी घोाणा करता हूं।

दूसरा, इन्होंने जो केप्टिव माइंस वगैरह चिरिया के संबंध में कहा है, यह जो मामला है, यह बात सही है कि हमने लोगों से बातचीत करने के बाद भी इसे रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद रिन्यूवल होनी चाहिए थी, उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था,

लेकिन रिजैक्ट कर दिया गया, जबकि हमारी उनसे बातचीत भी हो गई थी। उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गये हैं। जहां तक लॉस वगैरह का सवाल है, जो भी लॉस होगा, कुल मिलाकर हमें लगता है कि इस साल में 350 करोड़ रुपये का मुनाफा आयेगा। जो बाकी चीजें है, वह तो सार्ट आउट हो जायेगी और एक हजार करोड़ रुपया बच जायेगा। एक हजार करोड़ रुपये के लिए हम किसी के पास नहीं जाएंगे। स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मीट आउट करने के लिए सक्षम है। हमारे पास पैसा है, इसलिए पैसे के कारण हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, पैसा उसके रास्ते में नहीं आयेगा।

दूसरा आपने कुलटी के सम्बन्ध में कहा है। कुलटी का कारखाना घाटे में चल रहा था। उसमें 50 करोड़ रुपये हर साल का घाटा था और हमारे आने के पहले ऑलरेडी वह बन्द हो गया है। उसमें मुश्किल से कुछ कर्मचारी...(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : जो कुछ हुआ, वह हमारे कारण हुआ, आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए। पहले उसे आप लॉस में छोड़कर चले गये, उसे मैंने प्रोसेस किया था।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Only the Minister's reply will go on record.

*(Interruptions)** ...

श्री गुरुदास दासगुप्त : कुलटी के बारे में बताइये।

श्री रामविलास पासवान : एक मिनट।

MR. SPEAKER: Allow him to speak.

श्री रामविलास पासवान : मैं कुलटी का ही बता रहा हूं। कुलटी में मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 50 करोड़ रुपये का घाटा था। वह कम्पनी 1.4.2003 से बन्द कर दी गई। उसमें टोटल कर्मचारियों में से केवल 31 कर्मचारी बच गये हैं और बाकी 2861 कर्मचारियों को वी.आर.एस. देकर विदा कर दिया गया। यह फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार की नीयत में कोई कमी है, मैंने इस सदन में बार-बार कहा है कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीति कि कमी नहीं है, कमी नीयत की होती है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे कि सरकार की नीति भी सही है और सरकार की नीयत भी सही है। इससे कम समय में कोई भी सरकार इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकती है,

यह मैं चेलैंज के साथ कहता हूं। मैं घोाणा करता हूं कि अगले तीन महीने के अन्दर जो भी प्रक्रिया है, अध्यक्ष महोदय, आपका भी स्टेट है, उसे पूरी करके सारा काम समाप्त करके... (व्यवधान)

---

*Not Recorded.

श्री बसुदेव आचार्य : इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताइये।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन में सब कुछ कैसे हो जायेगा?

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are a very popular Minister today.

... (*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने दूसरी सब्सीडियरीज़ के बारे में कुछ नहीं किया।

श्री गुरुदास दासगुप्त : पासवान जी, कुलटी आपका सिद्धान्ततः बन्द ही रहेगा।

श्री रामविलास पासवान : जो चीज एक बार बन्द हो गई है और जिसे वी.आर.एस. देकर खत्म कर दिया गया है, उस सम्बन्ध में हम इस समय कुछ कहने से लाचार हैं। लेकिन जहां तक सेल का मामला है, सेल अभी प्रोफिट में है, इस्को भी हमारा प्रोफिट में है, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, रॉ-मैटीरियल भी है। हम इन सारे साधनों का प्रयोग करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसमें पैसा कहीं आड़े नहीं आयेगा ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Thank you very much. No more clarifications please.

श्री रामविलास पासवान : यह जो आपने कहा है कि असाधारण डिले हुई है, इसमें कोई डिले नहीं हुई है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए।

MD. SALIM (CALCUTTA – NORTH EAST): जहां तक आयरन ओर का मामला है, Iron ore is a raw material of national importance.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has said that and he has replied to that point. This is a different subject.

… (*Interruptions*)

मोहम्मद सलीम : यह तो केन्द्र सरकार का मामला है, मंत्री जी यहां सदन में हैं। झारखण्ड, उड़ीसा, गोवा और छत्तीसगढ़ में, जहां आयरन ओर में माफिया की तरफ काम हो रहा है और आयरन ओर विदेश भेजा जा रहा है, जबकि इस देश में स्टील की डिमांड है और स्टील फैक्टरीज़ के लिए इस देश में भी आयरन ओर चाहिए।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is not the way. Without my permission, certain things have been said and Mr. Minister, you are volunteering to reply without my permission.

… (*Interruptions*)

श्री रामविलास पासवान : इन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। आयरन ओर में बहुत घपला चल रहा था और चल रहा है। आयरन ओर का हमें मालूम है कि इस्को का कम दाम पर बेचा गया है, दूसरा आयरन ओर एक कम्पनी को एक दाम पर, दूसरी कम्पनी को दूसरे दाम पर और एक्सपोर्ट तीसरे दाम पर बेचा गया है। उसमें बिल्कुल पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं थी। हमने उसके लिए एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी को…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No more clarifications. Then the whole purpose is frustrated. This is not the way to deal with Calling Attention. He has given an assurance and I am sure that he will fulfil it.

श्री रामविलास पासवान : मैंने कहा है कि वह कमेटी इसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाये और काम में एकरूपता भी लाये, जिससे कम्पनी को भी फायदा हो और आम पब्लिक को भी फायदा हो।